





## मेडिकल कालेज का नाम प्यारेलाल के नाम पर न रखकर कांग्रेस ने कंवर समाज का किया अपमान - सरोज

प्रत्येक ग्राम पंचायत को 25-25 लाख देने की बातपर अडिंग

मुझे बाहरी कहने वाले

अपने नेताओं से क्यों

नहीं करते सवाल

कोरबा(विश्व परिवार)। कोरबा में मेडिकल कालेज की स्थापना की गई। कालेज का नाम अधिभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री प्यारेलाल कंवर के नाम पर न रखकर कांग्रेस ने कंवर समाज का अपमान किया है। स्व. कंवर ने जिले में मेडिकल कालेज का सपना देखा था। कांग्रेस में परिवारवाद ही रहा है। ऊपर गांधी तो नीचे महंत परिवार है। ऊपर गांधी कांग्रेस में और कोई नेता नहीं है। लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम को 25-25 लाख रुपये देने की बात पर अडिंग हूँ। इस राशि से ग्राम



पंचायतों का विकास कराएंगे। उक्त बांधे टीपी नगर में आयोजित पत्रकरवातों के द्वारा भाजपा की राष्ट्रीय उपायक्षम व कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सुश्री सरोज

पांडेय ने कहा। सुश्री पांडेय ने उक्त बांधे करे जाने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी के द्वारा लगातार बाहरी का मुद्दा उत्तरा जा रहा है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ क्या उनके राष्ट्रीय नेता जहां पर वह बोट डालते हैं वह वहां से चुनाव लड़ते हैं। राहुल

गांधी कभी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और कभी बायानाड़ से चुनाव लड़ते हैं। स्वयं छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व गृहमंत्री तापाध्वज सालू महासंस्कृत से चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र यादव जो भिलाई के विधायक हैं वह बिलासपुर से लड़ रहे हैं क्या उनसे यह सवाल कर सकती है सीधे तौर पर कहूँ जाने में उनकी हार की ज़ु़नालाहट उनके चेहरे और उनके क्षेत्र में बोट डालते हैं, मैं उनके पूछना चाहती हूँ क्या उनके राष्ट्रीय मौदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में जो कार्य हुए हैं वह ऐतिहासिक व हितग्राही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। कोरबा में 2014 में 2573 किलोमीटर तक की सड़क का सोच निर्णय से देश में हर वर्ग का निर्माण हुआ था।

जीवन स्तर सुधारा व आत्म निर्भर बना है अगर हम कोरबा की बात करें 2019 में जल जीवन मिशन योजना के तहत 22092 हितग्राही थे। वर्तमान 2023 तक 305387 हितग्राही है, प्रधानमंत्री आवास योजना 3106 हितग्राही 2019 में थे। 2023 तक 115013 हितग्राही है, प्रधानमंत्री किसान सम्पन्न निधि योजना के तहत कोरबा लोक सभा के 196890 अन्नदाता भाइयों के खाते में राशि हस्तांतरण की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2016 में 234182 हितग्राही थे। वर्तमान 2024 में 2684564 हितग्राही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। कोरबा में 2014 में 2573 किलोमीटर तक की सड़क का निर्माण हुआ था।

## कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी पर जनता को पूरा भरोसा

गणेश महिलाओं को 8333 रुपए, आंगनबाड़ी वर्करों, आशा, मिड-डे-मिल कर्मियों को देंगे दोगुना मानदेय



उठाने के लिए नारी न्याय महालक्ष्मी योजना में हर महिने 8333 रुपए दिया जाएगा जो गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए जाएंगे। ज्योत्स्ना महंत ने कहा कि न्याय पत्र पर महिलाओं ने अपना भरोसा जताया है और इसे पसंद कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में 50 प्रतिशत अरक्षण का लाभ दिया गया है। शक्ति का समान करते हुए आशा, मिड-डे-मिल व आंगनबाड़ी वर्करों को दोगुना

मानदेय दिया जाएगा। साविकी बाई फुले हॉस्टल योजना में कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल बनाए जाएंगे। ज्योत्स्ना महंत ने कहा कि न्याय पत्र पर महिलाओं ने अपना भरोसा जताया है और इसे पसंद कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में सरकार की नीरी की केंद्र सरकार के द्वारा नहीं प्रदायिकरी व कार्यकर्ताओं की उपरिधिक्षित लगातार बनी है। कांग्रेस की

सरकार आगे पर 30 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। सांसद ने कहा कि मर्हांडी और बेरोजगारी से छुटकारा एकमात्र कांग्रेस की सरकार ही कर सकती है और इसके लिए केंद्र में सरकार बनाना है। ज्योत्स्ना महंत ने कहा कि न्याय पत्र के द्वारा नहीं प्रतिशत अपथ्य के विषय में विशेष जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। जिसे अपाकार के ने केवल स्वस्थ रह सकें। इसके नारी-वर्ग के लिए रोगीय अपितृ परेशान भी हो सकेंगे। मासानुसार आहार सेवन स्थानीय पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बताते हुये डॉ. नागेन्द्र नारायण शर्मा पर उपरिधिक्षित लगातार बनी है।

उठाने के लिए नारी न्याय महालक्ष्मी योजना में हर महिने 8333 रुपए दिया जाएगा जो गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए जाएंगे। ज्योत्स्ना महंत ने कहा कि न्याय पत्र पर महिलाओं ने अपना भरोसा जताया है और इसे पसंद कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में सरकार की नीरी की केंद्र सरकार के द्वारा नहीं प्रदायिकरी व कार्यकर्ताओं की उपरिधिक्षित लगातार बनी है। कांग्रेस की

सरकार आगे पर 30 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। सांसद ने कहा कि मर्हांडी और बेरोजगारी से छुटकारा एकमात्र कांग्रेस की सरकार ही कर सकती है और इसके लिए केंद्र में सरकार बनाना है। ज्योत्स्ना महंत ने कहा कि न्याय पत्र के द्वारा नहीं प्रतिशत अपथ्य के विषय में विशेष जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। जिसे अपाकार के ने केवल स्वस्थ रह सकें। इसके नारी-वर्ग के लिए रोगीय अपितृ परेशान भी हो सकेंगे। मासानुसार आहार सेवन स्थानीय पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बताते हुये डॉ. नागेन्द्र नारायण शर्मा पर उपरिधिक्षित लगातार बनी है।

उठाने के लिए नारी न्याय महालक्ष्मी योजना में हर महिने 8333 रुपए दिया जाएगा जो गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए जाएंगे। ज्योत्स्ना महंत ने कहा कि न्याय पत्र पर महिलाओं ने अपना भरोसा जताया है और इसे पसंद कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में सरकार की नीरी की केंद्र सरकार के द्वारा नहीं प्रदायिकरी व कार्यकर्ताओं की उपरिधिक्षित लगातार बनी है। कांग्रेस की

सरकार आगे पर 30 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। सांसद ने कहा कि मर्हांडी और बेरोजगारी से छुटकारा एकमात्र कांग्रेस की सरकार ही कर सकती है और इसके लिए केंद्र में सरकार बनाना है। ज्योत्स्ना महंत ने कहा कि न्याय पत्र के द्वारा नहीं प्रतिशत अपथ्य के विषय में विशेष जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। जिसे अपाकार के ने केवल स्वस्थ रह सकें। इसके नारी-वर्ग के लिए रोगीय अपितृ परेशान भी हो सकेंगे। मासानुसार आहार सेवन स्थानीय पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बताते हुये डॉ. नागेन्द्र नारायण शर्मा पर उपरिधिक्षित लगातार बनी है।

उठाने के लिए नारी न्याय महालक्ष्मी योजना में हर महिने 8333 रुपए दिया जाएगा जो गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए जाएंगे। ज्योत्स्ना महंत ने कहा कि न्याय पत्र पर महिलाओं ने अपना भरोसा जताया है और इसे पसंद कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में सरकार की नीरी की केंद्र सरकार के द्वारा नहीं प्रदायिकरी व कार्यकर्ताओं की उपरिधिक्षित लगातार बनी है। कांग्रेस की

सरकार आगे पर 30 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। सांसद ने कहा कि मर्हांडी और बेरोजगारी से छुटकारा एकमात्र कांग्रेस की सरकार ही कर सकती है और इसके लिए केंद्र में सरकार बनाना है। ज्योत्स्ना महंत ने कहा कि न्याय पत्र के द्वारा नहीं प्रतिशत अपथ्य के विषय में विशेष जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। जिसे अपाकार के ने केवल स्वस्थ रह सकें। इसके नारी-वर्ग के लिए रोगीय अपितृ परेशान भी हो सकेंगे। मासानुसार आहार सेवन स्थानीय पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बताते हुये डॉ. नागेन्द्र नारायण शर्मा पर उपरिधिक्षित लगातार बनी है।

उठाने के लिए नारी न्याय महालक्ष्मी योजना में हर महिने 8333 रुपए दिया जाएगा जो गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए जाएंगे। ज्योत्स्ना महंत ने कहा कि न्याय पत्र पर महिलाओं ने अपना भरोसा जताया है और इसे पसंद कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में सरकार की नीरी की केंद्र सरकार के द्वारा नहीं प्रदायिकरी व कार्यकर्ताओं की उपरिधिक्षित लगातार बनी है। कांग्रेस की

सरकार आगे पर 30 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। सांसद ने कहा कि मर्हांडी और बेरोजगारी से छुटकारा एकमात्र कांग्रेस की सरकार ही कर सकती है और इसके लिए केंद्र में सरकार बनाना है। ज्योत्स्ना महंत ने कहा कि न्याय पत्र के द्वारा नहीं प्रतिशत अपथ्य के विषय में विशेष जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। जिसे अपाकार के ने केवल स्वस्थ रह सकें। इसके नारी-वर्ग के लिए रोगीय अपितृ परेशान भी हो सकेंगे। मासानुसार आहार सेवन स्थानीय पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बताते हुये डॉ. नागेन्द्र नारायण शर्मा पर उपरिधिक्षित लगातार बनी है।

उठाने के लिए नारी न्याय महालक्ष्मी योजना में हर महिने 8333 रुपए दिया जाएगा जो गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से मज

# संपादकीय जलवायु परिवर्तन और भारतीय चुनाव.....

## आरक्षण का मुद्दा गरमाया

चुनाव प्रचार में इन दिनों आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। प्रारंभिक तौर पर आरक्षण को सबसे निचले वर्गों की जातियों को आर्थिक तथा राजनीतिक संबल प्रदान करने के लिए वैधानिक तौर पर आरक्षण प्रदान किया गया था। बाद में आरक्षण का विस्तार होता गया और इसमें नये-नये जाति समूह शामिल होते चले गए। आरक्षण प्राप्त करने के लिए जट और मराठा जैसे शक्तिशाली समूहों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी। दरअसल, जो आरक्षण निचली पायदान पर खड़े जाति समूहों के उत्थान के लिए था, वह सभी जाति समूहों के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का हथियार बन गया। कहने की जरूरत नहीं है कि आज आरक्षण भारतीय समाज के एक बहुत बड़े वर्ग में असंतोष और चिंता का कारक बना हुआ है। हिन्दू समाज के अनारक्षित जाति समूह मानते हैं कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। ऐसी सूरत में एक ऐसे आर्थिक ढांचे पर बल दिए जाने की जरूरत थी जिसमें बिना आरक्षण की सीढ़ी के सभी निचले वर्ग के लोगों को उत्थान के अवसर प्राप्त हों और जातीय आग्रह समाजिक विग्रह के कारण न बनें लेकिन अब आरक्षण की नीति एक चिंताजनक मोड़ पर ले आई है। एक ओर, जहां कांग्रेस के नेता विशेषकर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी हर सभा में कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आरक्षण को मुस्लिम तुष्टिकरण का नया औजार बना लिया है। वह बार-बार कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं जहां कांग्रेस ने सभी मुस्लिम जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करके पिछड़े वर्ग के कोटे से ही 4 प्रतिशत का आरक्षण दे दिया जिसे बाद में भाजपा सरकार ने निरस्त कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां भाजपा सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गई है। मोदी अपनी हर सभा में खुलकर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो दलित और पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर मुसलमानों को दे देगी। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने चोर दरवाजे से कर्नाटक में आरक्षण देकर जो कदम उठाया है, उसके दुष्परिणाम समझ नहीं पा रही। बेशक, भाजपा को विरोध का बड़ा चुनावी मुद्दा मिल गया है।



की गति तेज हुई है। तापमान वृद्धि से समुद्र का जल भी ज्यादा गर्म हो रहा है जिसके कारण भारी बारिश और समुद्री तूफानों का खतरा बढ़ा है। पिछले चार दशकों में अब सापर में समुद्री तूफानों की संख्या में डेढ़ गुणा वृद्धि हुई है और तूफानों की घातकता भी बढ़ी है। जुलाई और अगस्त 2023 में हिमाचल और उत्तराखण्ड में भारी बारिश के कारण भूस्खलन के कारण हुई भारी तबाही का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है जिसको भारत सरकार ने आपात स्थिति घोषित किया। इन स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन के विषय में भी काफ़ी कुछ करने की जरूरत पर रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है। हालांकि भारत ने इस विषय में कुछ मानकों पर अच्छी प्रगति की है, परं भी काफ़ी कुछ किए जाने की जरूरत है। पूर्व चेतावनी व्यवस्था में सुधार करके आपदाओं में होने वाली हानि को 30 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। रिपोर्ट में आर्थिक असमानता के चलते जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के और ज्यादा चिंताजनक होने की बात कही गई है। जाहिर है कि बढ़ते तापमान का प्रत्यक्ष ढंक उन गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है जिनके पास आवास की व्यवस्था नहीं है या जिन्हें दैनिक मजदूरी पर निर्भर

रहना पड़ता है, या किसान जिनकी फसल खुले में इश्वर भरोसे रहती है। उनके लिए जलवायु अनुकूलन व्यवस्था खड़ी करना भी संभव नहीं होता। बढ़ते तापमान से फसलों की उत्पादकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा पैदा होने की संभावना बन सकती है। इस दिशा में जलवायु की विपरीत स्थितियों को झेलने में सक्षम फसलों और फसल किस्मों पर ज्यादा शोध और प्रचार प्रसार की जरूरत है। इस दिशा में पुराने समय में प्रचलित श्री धार्य फसलों कोदा, रामदाना, स्वांक, बाजरा आदि का प्रचार प्रसार करके अच्छी पहल की जा रही है। किन्तु कार्बन उत्सर्जन करने वाली ऊर्जा उत्पादन तकनीकों और बड़े प्रोजेक्टों, खनन परियोजनाओं के कारण वनों के विनाश से कार्बन प्रचूरण क्षमता में आ रही कमी की चुनौतियां यथावत बनी हैं और बढ़ भी रही हैं। पिछले 15 वर्षों में भारतवर्ष में 3 लाख हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग इस तरह की बृद्धाकार योजनाओं के लिए बदला जा चुका है और यह क्रम सतत रूप से जारी है। इनी चिंताजनक स्थिति के बावजूद वर्तमान चुनावों में यह मुद्दा जनता के बीच महत्वपूर्ण नहीं बन सका है। पर्यावरण से जुड़े दिवसों पर चेतना रेली निकालने, कुछ अच्छे अच्छे नारे लगाने,

भाषण प्रतियोगिता आयोजित करने या ज्यादा से ज्यादा चुनाव मैनिफेस्टो में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े वादे उछलने तक हम सीमित होते जा रहे हैं। राजनीतिक दल भी जनचेतना जगाने के इस मौके का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आम मतदाता निजी आर्थिक लाभ से ज्यादा सोचने को तैयार नहीं हैं। इसलिए राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हिमालय के नाजुक परिस्थिति संतुलन के दृष्टिगत यह मामला हिमालय में और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। किन्तु हम प्राकृतिक आपदा का बहाना घड़ कर आत्म संतुष्टि कर लेते हैं या खुद को धोखा देते रहते हैं, जबकि हम सब समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन मानव निर्मित गलतियों का नतीजा है। पिछे भी हम न तो आत्म संयम से अनावश्यक वस्तुओं, पदार्थों के उपयोग से बचना चाहते हैं, न ही सरकारों के सामने अपनी पर्यावरण विषयक चिंताओं को रख कर दबाव बना कर नीतिगत बदलाव की मांग रखना चाहते हैं। सरकारों अपने आप विकास को सकल घेरू उत्पाद वृद्धि दर से नाप कर आगे बढ़ती हैं। उन्हें पर्यावरण जैसे मुद्दे उतने लुभावने नहीं लगते। दुनिया भर में सरकारें जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर टालमटोल करते हुए, शर्मित हुए कुछ थोड़ा बहुत कार्य करती रहती हैं। कुछ गंभीरता जब आपदाएं आती हैं तब दिखाई देती है, धीरे धीरे प्रकृति के ऊपर दोपारोपण करके समस्या भूल जाती है। इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही इस मुद्दे पर कुछ लक्ष्य अपने चुनावी मैनिफेस्टो में रखे हैं। किन्तु पिछले अनुभव के आधार पर ज्यादा आशा नहीं जगती है। शिमला में 2009 में जलवायु कॉन्क्लेव हुआ था, उसके साथ ही हिमालयी परिस्थिति तंत्र को बचाने के लिए कुछ लक्ष्य तय किए गए थे, किन्तु दोनों प्रमुख दलों को पर्याप्त समय मिलने के बावजूद विशेष प्रगति इस दिशा में नहीं हो सकी। वैश्विक स्तर और हिमालय के स्तर पर जलवायु परिवर्तन की चुनावी के कारण बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के चलते अब समय आ गया है जब इस मुद्दे पर आम जनता और राजनीतिक दलों को चुनावी राजनीति के केंद्र में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को रखना चाहिए।

## विशेष लेख

# इंतजामों को अधिक सक्रिय करने की जरूरत है.....

हमारे देश के वनों में गर्मियों के दिनों में आग लगना एक लगातार सिलसिला है। अप्रैल का महीना शुरू हुआ कि आग से जंगल धधकने लगते हैं। जंगल की आग पर्यावरण की दृष्टि से तो खतरनाक है ही जनजीवन और बायोडायर्वर्सिटी की दृष्टि से भी हानिकारक है। ऐसे समय में जब जंगलों में आग लगती है तो देखा गया है कि उसकी तैयारी में सरकार विफल रही है। देश के वनों में अप्रैल माह में आग की घटनाओं को देखें तो देश में हाल फिलहाल 361 जगह वनों में आग लगी हैं। इन घटनाओं की निगरानी को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की साइट पर लांच बीटा संस्करण एसएनीपी - बीआईआईआरएस का 10 अप्रैल, 2024 का भारत के वनों में लगी भीषण आग का मौजूद आंकड़ा बताता है कि सबसे अधिक आंश्र प्रदेश में 122, तेलंगाना में 55, छत्तीसगढ़ में 47, उत्तराखण्ड में 32, बिहार में 23, ओडिशा में 22, उत्तर प्रदेश में 17 सहित 21 राज्यों में 361 जगह आग लगी थी जो 13 अप्रैल को घट कर काबू होने के बाद 33 रह गई है। 13 अप्रैल को देश के वनों में 132 बड़ी आग लगी थी जो 10 अप्रैल को 361 जगह तक पहुंच गई है। अप्रैल माह में पिछले 7 दिनों का आंकड़ा देखें तो एक्टिव आग की घटनाओं में टॉप फाइव राज्यों में छत्तीसगढ़ में 166, आंश्र प्रदेश में 248, मध्य प्रदेश में 207, ओडिशा में 146 और असम में 139 जगहों पर बड़ी आग लगी। वहीं 1 नवम्बर, 2023 से 2024 में बड़ी आग की घटनाओं में टॉप फाइव राज्यों में आंश्र प्रदेश में 860, मध्य प्रदेश में 719, तेलंगाना 688, महाराष्ट्र में 547 और छत्तीसगढ़ में 527 बार आग लगी, जबकि वर्ष 2022-2023 में तो पूरे देश के वनों में 12562 आग की घटनाएं हुईं। जंगल की आग से वनों का क्षरण तो होता ही है बहुमूल्य वन संपदा और कार्बन

का कारण बन रही जहरीली शाराब का अवैध कारबोबार नेस्तानबूद करना होगा इतिहास साक्षी रहा है कि मदिरा की तिजारत, खपत व मांग में कभी कमी नहीं आई है। मद्यपान का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। सुरापान का प्रचलन समाज में हर वर्ग के लोगों में व्यापक रहा है। आचार्य चार्वाक जैसे महान् दर्शनिक ने सदियों पूर्व अपने श्लोकों में सुरापान का उल्लेख किया था। मदिरा की नशीली तासीर को कई शायर व फनकार अपने अंदाज में बयान करते आए हैं। 'हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है'- अकबर इलाहाबादी के इन अल्फज को पाकिस्तान के मशहूर गायक 'गुलाम अली' ने अपनी आवाज से बयान करके सुरा प्रेमियों को नसीहत देकर चेताया था। जाहिर है मदिरा का सेवन हो, अवैध तिजारत हो या देर रात तक खुली रहने वाली मधुशालाओं में आब-ए-तल्ख बोतलों में सजी हो, मदिरा हंगामा जरूर मचाती है। वर्तमान में आब-ए-तल्ख के घोटाले को लेकर देश की राजधानी चर्चा का मरकज बन चुकी है। देश में चुनावों का दौरा चल रहा है। आबकारी विभाग व अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अवैध शराब को कब्जे में लेने की खबरें समाचारपत्रों की सुर्खियां बन रही हैं। मद्यपान के प्रति निगाह-ए-नाज के जज्बात रखने वाला मदिरा प्रेमी वर्ग सुरापान को आब-ए-ह्यात मानता है, चूंकि आब-ए-तल्ख

सारा प्रेमियों को एक काल्पनिक दुनिया के हसीन ख्वाब दिखाती है। मदिरा की तिजारत को हमारी हुक्मूमतें अर्थतंत्र की मजबूती का जरिया मानती हैं। अल्कोहल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से राज्य सरकारों को एक बड़ा राजस्व हासिल होता है। इसलिए सियासी निजाम शराब को नशा नहीं मानता। मगर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन बिगाड़ने वाली शराब किस हद तक अपना दुष्परिणाम दिखाती है, यह छिपा नहीं है। गत ग्यारह अप्रैल 2024 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक निजी स्कूल वैन के भीषण हादसे का शिकार होने से आठ मासूम छात्रों की मौत हो गई, क्योंकि स्कूल वैन का चालक शराब के नशे में धुत था। अवैध शराब के जहरनुमां कारोबार ने कई घरों के चश्म-ओ-चिराग बुझाकर लाखों लोगों की शब-ए-महताब को जुल्मत में तब्दील कर दिया है। 22 मार्च 2024 को पंजाब के संग्रहर जिले में बीस से ज्यादा लोगों की मौत का कारण जहरनुमां शराब बनी। संग्रहर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व चुनाव आयोग भी हरकत में आ गए। जहरीली शराब देश में एक मुहूर्त से मौत का तांडव मचा रही है। लेकिन नशे के अजाब से उपजे मातम को शांत करने के लिए पीड़ितों के आब-ए-चश्म पर मुआवजे व सियासी आश्वासनों का मरहम लगा कर मसले को रफ्फ दफ्फ किया जाता है। चश्म-ए-पलक की रौशनी छीनकर चश्मों की सौगात बांटने की कोशिश होती है। शराब तस्करी पर प्रशासन व

शरक्षा एजेंसियों की नाकामी को छुपाने के प्रयास किए जाते हैं। आर्थिक तंगी के कारण कई लोग शराब माफिया के प्रलोभन में आकर सस्ते दामों पर मिलने वाली नकली शराब खरीद लेते हैं। अवैध शराब ही मौत का कारण बनती है। गुरुबत में जीवनयापन करने वाले लोग अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ने में असमर्थ होते हैं। इसी कारण सैकड़ों लोगों को मौत की आगोश में सुलाने वाले नशे के सरगना कानूनी दांवपेंच से बच निकल कर अपनी नशे की सलतनत को बेखौफ होकर चलाते हैं। देश में नशा उन्मूलन के नाम पर कई विशेष दिवस मनाए जाते हैं। नशा मुक्ति केन्द्रों का संचालन भी हो रहा है। वहाँ मरम्याखानों की संख्या में भी रिकार्ड वृद्धि दर्ज हो रही है। शादी समारोहों में होने वाला फ्साद व सड़कों पर कहर मचाती तेज रफ्तार से बढ़ती दुर्घटनाएं, घरेलू हिंसा तथा सामाजिक परिवेश में बढ़ती आपाराधिक गतिविधियों के पीछे ज्यादातर पसमंजर मद्यापन का ही है। त्योहार, पर्व के अवसर पर मदिरा की डिमांड जोर पकड़ लेती है। कई राज्यों के चुनावों में नशे का समूल नाश भी एक अहम मुद्दा बनता है। नशे की गिरफ्त में जा रहे मुल्क के मुस्तकबिल युवा वर्ग पर चिंता व्यक्त की जाती है, मगर मदिरा के इस्तेमाल के बिना इंतेहाबी तश्हीर की दर्जा-ए-हरारत अधूरी रहती है। भारत का शराब उद्योग दुनिया में सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। देश के कुछ राज्यों में शराबबंदी जरूर हुई है, लेकिन हकीकत में कोई भी राज्य तथा अवाम ईमानदारी से शराब निषेध के पक्ष में

नहीं है। इसलिए कई राज्यों में मद्यनिषेध के प्रयास असफल हुए। शराबबंदी का एक लंबा सप्त तय करने वाले राज्य गुजरात में सुरा प्रेमी सन् 2018 से गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएँ दर्ज करके शराबबंदी को चुनौती पेश कर रहे हैं। एक देश एक कानून का हवाला देकर शराब निषेध कानून को राज्य से रुखसंत करने की मांग हो रही है। सुरा प्रेमियों की दलील है कि शराब पीने को भी 'राइट टु प्राइवेसी' के तहत बुनियादी अधिकार माना जाए। याचिकाओं में यह भी तर्क है कि 'गुजरात निषेध अधिनियम 1949' राज्य में मदिरा की अवैध तिजारत रोकने में अप्रभावी है। बिहार राज्य में भी शराबबंदी को न्यायालय में चुनौती मिल चुकी है, लेकिन भारत में शराब राज्य का अपना विषय है। संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत प्रत्येक राज्य को मादक पेय व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध का अधिकार है। राजस्व जुटाने के लिए किसी सूबे को आब-ए-तल्ख की दारुल हुक्मत बनाकर लोगों को नशे की दलदल में उतार देना कितना उचित है, इस मुद्दे पर मंथन होना चाहिए। स्परण रहे सुरा प्रेमियों की ख्वाहिश के आगे बैबस होकर अमरीका तथा सोवियत संघ जैसे देशों ने शराबबंदी के फैसले रद्द कर दिए थे। बहरहाल कई परिवारों की बर्बादी का अस्बाब बन चुकी जहरीली मदिरा की अवैध तिजारत शराब माफियाओं के लिए फयदेमंद बिजनेस बन चुकी है। शराब की तस्करी व अवैध बिक्री मुक्त में अस्थिरता का तनाजुर पैदा कर रही है।

# आब-ए-तल्ख की तिजारत अपराध को दावत

शराब की तस्करी व अवैध विक्री मुल्क में अस्थिरता का तनाजुर पैदा कर रही है। लिहाजा समाज में अमन कायम करने के लिए सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बन रही जहरीली शराब का अवैध कारोबार नेस्तनाबूद करना होगा इतिहास साक्षी रहा है कि मदिरा की तिजारत, खपत व मांग में कभी कमी नहीं आई है। मद्यपान का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। सुरापान का प्रचलन समाज में हर वर्ग के लोगों में व्यापक रहा है। आचार्य चार्वाक जैसे महान् दार्शनिक ने सदियों पूर्व अपने श्लोकों में सुरापान का उल्लेख किया था। मदिरा की नशीली तासीर को कई शायर व फक्तकर अपने अंदाज में बयान करते आए हैं। 'हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है'- अकबर इलाहाबादी के इन अल्फ्यूज को पाकिस्तान के मशहूर गायक 'गुलाम अली' ने अपनी आवाज से बयान करके सुरा प्रेमियों को नसीहत देकर चेताया था। जाहिर है मदिरा का सेवन हो, अवैध तिजारत हो या देर रात तक खुली रहने वाली मधुशालाओं में आब-ए-तत्ख बोतलों में सजी हो, मदिरा हंगामा जरूर मचाती है। वर्तमान में आब-ए-तत्ख के घोटाले को लेकर देश की राजधानी चर्चा का मरकज बन चुकी है। देश में चुनावों का दौर चल रहा है। आबकारी विभाग व अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अवैध शराब को कज्जे में लेने की खबरें समाचारपत्रों की सुर्खियां बन रही हैं। मद्यपान के प्रति निगाह-ए-नाज के जब्बात रखने वाला मदिरा प्रेमी वर्ग सुरापान को आब-ए-ह्यात मानता है, चूंकि आब-ए-तत्ख

सुरा प्रेमियों को एक काल्पनिक दुनिया के हसीन खाब दिखाती है। मदिरा की तिजारत को हमारी हुक्मतें अर्थतंत्र की मजबूती का जरिया मानती हैं। अल्कोहल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से राज्य सरकारों को एक बड़ा राजस्व हासिल होता है। इसलिए सियासी निजाम शराब को नशा नहीं मानता। मगर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन बिगाड़ने वाली शराब किस हद तक अपना दुष्परिणाम दिखाती है, यह छिपा नहीं है। गत ग्यारह अप्रैल 2024 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक निजी स्कूल वैन के भीषण हादसे का शिकार होने से आठ मासूम छात्रों की मौत हो गई, क्योंकि स्कूल वैन का चालक शराब के नशे में धृत था। अवैध शराब के जहरनुमां कारोबार ने कई घरों के चश्म-ओ-चिरण बुझाकर लाखों लोगों की शब-ए-महताब को जुल्मत में तब्दील कर दिया है। 22 मार्च 2024 को पंजाब के संगरूर जिले में बीस से ज्यादा लोगों की मौत का कारण जहरनुमां शराब बनी। संगरूर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व चुनाव आयोग भी हरकत में आ गए। जहरीली शराब देश में एक मुहूर से मौत का तांडव मचा रही है। लेकिन नशे के अजाब से उपजे मातम को शांत करने के लिए पीड़ितों के आब-ए-चश्म पर मुआवजे व सियासी आश्वासनों का मरहम लगा कर मसले को रफ्फ दफ्फ किया जाता है। चश्म-ए-पलक की रौशनी छीनकर चश्मों की सौगात बाटने की कोशिश होती है। शराब तस्करी पर प्रशासन व

सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी का छुपाने के प्रयास किए जाते हैं। आर्थिक तंगी के कारण कई लोग शराब माफिया के प्रलोभन में आकर सस्ते दामों पर मिलने वाली नकली शराब खरीद लेते हैं। अवैध शराब ही मौत का कारण बनती है। गुर्बत में जीवनयापन करने वाले लोग अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ने में असमर्थ होते हैं। इसी कारण सैकड़ों लोगों की मौत की आगोश में सुलाने वाले नशे के सरगना कानूनी दांवपंच से बच निकल कर अपनी नशे की सल्तनत को बेखाफ़ होकर चलाते हैं। देश में नशा उम्मूलन के नाम पर कई विशेष दिवस मनाए जाते हैं। नशा मुक्ति केन्द्रों का संचालन भी हो रहा है। वहीं मयखानों की संख्या में भी रिकार्ड वृद्धि दर्ज हो रही है। शादी समारोहों में होने वाला फ्साद व सड़कों पर कहर मचाती तेज रफ्तार से बढ़ती दुर्घटनाएं, घेरे लूंहिंसा तथा सामाजिक परिवेश में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के पीछे ज्यादातर पसमंजर मद्यपान का ही है। त्योहार, पर्व के अवसर पर मदिरा की डिमाड जौर पकड़ लेती है। कई राज्यों के चुनावों में नशे का समूल नाश भी एक अहम मुद्दा बनता है। नशे की गिरफ्त में जा रहे मुल्क के मुस्तकबिल युवा वर्ग पर चिंता व्यक्त की जाती है, मगर मदिरा के इस्तेमाल के बिना इंतेहाबी तश्हीर की दर्जा-ए-हरारत अधूरी रहती है। भारत का शराब उद्योग दुनिया में सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। देश के कुछ राज्यों में शराबबंदी जरूर हुई है, लेकिन हकीकत में कोई भी राज्य तथा अवाम ईमानदारी से शराब निषेध के पक्ष में

नहीं है। इसलिए कई राज्यों में मदनिषेध के प्रयास असफल हुए। शराबबंदी का एक लंबा सप्त तय करने वाले राज्य गुजरात में सुरा प्रेमी सन् 2018 से गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएं दर्ज करके शराबबंदी को चुनौती पेश कर रहे हैं। एक देश एक कानून का हवाला देकर शराब निषेध कानून को राज्य से रख सत करने की मांग हो रही है। सुरा प्रेमियों की दलील है कि शराब पीने को भी 'राइट टु प्राइवेसी' के तहत बुनियादी अधिकार माना जाए। याचिकाओं में यह भी तर्क है कि 'गुजरात निषेध अधिनियम 1949' राज्य में मदिरा की अवैध तिजारत रोकने में अप्रभावी है। बिहार राज्य में भी शराबबंदी को न्यायालय में चुनौती मिल चुकी है, लेकिन भारत में शराब राज्य का अपना विषय है। संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत प्रत्येक राज्य को मादक पेय व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध का अधिकार है। राजस्व जुटाने के लिए किसी सूबे को आब-ए-तल्ख की दारुल हुक्मपत्र बनाकर लोगों को नशे की दलदल में उतार देना कितना उचित है, इस मुद्दे पर मंथन होना चाहिए। स्मरण रहे सुरा प्रेमियों की ख्वाहिश के आगे बेबस होकर अमरीका तथा सोवियत सघ जैसे देशों ने शराबबंदी के फैसले रद्द कर दिए थे। बहरहाल कई परिवारों की बर्बादी का अस्वाक बन चुकी जहरीली मदिरा की अवैध तिजारत शराब मपियाओं के लिए फयदेमंद बिजनेस बन चुकी है। शराब की तस्करी व अवैध बिक्री मुल्क में अस्थिरता का तनाजुर पैदा कर रही है।

# वैश्विक अंचाई पर खिलौना कारोबार

डा. जयंतीलाल भंडारी

अधिकांश भारतीय खिलौने ई-कॉर्मर्स वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि घरेलू खिलौनों की बिक्री को और बढ़ाया जा सके। यह भी जरूरी है कि सरकार के द्वारा प्रस्तावित की गई पारंपरिक और यांत्रिक खिलौनों दोनों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शीघ्र शुरू की जाए। देश में सुगठित खिलौना प्रशिक्षण और डिजाइन संस्थान की स्थापना को मूर्तरूप देना होगा हाल ही में केंद्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारत के खिलौना उद्योग ने वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2022-23 के बीच तेजी से प्रगति की है और निर्यात में 239 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई तथा आयात में 52 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। निःसंदेह इस समय पूरी दुनिया में यह रेखांकित हो रहा है कि 'मेक इन इंडिया' अभियान से भारत का खिलौना उद्योग वैश्विक ऊँचाई पर है। स्थिति यह है कि 'मेक इन इंडिया' अभियान ने खिलौना विनिर्माण क्षेत्र में चीन को झटका देते हुए खिलौना निर्माण को भारत के लिए पर्यादे का सौदा साबित कर दिया है। गौरतलब है कि चीन से खिलौनों की खरीददारी करने वाले कई खरीदार अब तेजी से भारत की ओर रुख कर रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है कि दुनिया में कोई एक दशक पहले खिलौनों की भारत से मुश्किल से ही किसी तरह की खरीददारी होती थी। लेकिन मेक इन इंडिया के कारण कई बड़ी-बड़ी खिलौना कंपनियों ने भारत में खास तौर से दिल्ली में अपना आधार तैयार किया है, जो आज अंतरराष्ट्रीय खिलौना कंपनियों को भी आकृति करती है। इस समय हैस्ट्रो, मैटल, स्पिन मास्टर और अर्ली लॉर्निंग सेंटर जैसे खिलौनों के वैश्विक ब्रांड आपूर्ति के लिए भारत पर अधिक निर्भर हैं। साथ ही खिलौनों के लिए विश्व प्रसिद्ध इटली की दिग्गज कंपनी ड्रीम प्लास्ट, माइक्रोप्लास्ट और इंकास आदि



खिलौनों के लिए अपना ध्यान धीरे-धीरे चीन से भारत पर केंद्रित कर रही हैं। अब वह समय बीत गया है कि जब पांच-छह वर्ष पहले तक भारत खिलौनों के लिए बहुत कुछ दूसरे देशों पर निर्भर था और भारत में 80 प्रैसदी से अधिक खिलौने चीन से आयात किए जाते थे। साथ ही लगातार विभिन्न सर्वेक्षणों में कहा जा रहा था कि चीन से आयातित दो-तिहाई खिलौने असुरक्षित थे। चीनी खिलौने में सीसा, कैडमियम और बेरियम के असुरक्षित तत्व पाए गए थे। अब भारत से खिलौनों के तेजी से बढ़ते हुए निर्यात और घटते हुए आयात का नया लाभप्रद अध्याय भी रेखांकित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि इस समय देश और दुनिया में भारतीय खिलौना उद्योग की बहुत कम समय में हासिल ऐसी सफलता रेखांकित हो रही है, जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इस समय चारों ओर भारत के सस्ते और गुणवत्तापूर्ण खिलौना उद्योग का सुकूनदेह परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहा है। साथ ही भारत का खिलौना निर्यात पांच-छह वर्षों में तेजी से बढ़कर 2600 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। भारत से अमरीका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, आस्ट्रेलिया, यूरई, दक्षिण

अमेरिका सहित कई देशों को खिलौने ने निर्यात किए जा रहे हैं। इस समय भारतीय खिलौना उद्योग का कारोबार करीब 1.5 अरब डॉलर का है जो वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 0.5 फीसदी मात्र है, लेकिन जिस तरह भारत में खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उससे खिलौना उद्योग छलांग लगाकर बढ़ते हुए इसी वर्ष 2024 में 3 अरब डॉलर तक की ऊंचाई पर पहुंचने की संभावनाएं रखता है। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि देश और दुनिया में भारतीय खिलौना बाजार को ऊंचाई मिलने के कई कारण हैं। इसमें कोई मत नहीं है कि 'मन की बात' के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार देश के लोगों को स्वदेशी भारतीय खिलौनों को खरीदने, घरेलू डिजाइनिंग को सुदृढ़ बनाने, भारत को खिलौनों के लिए एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाने की अपील की। खिलौनों की बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की मंजूरी जरूरी होना, संरक्षणवाद, चीन-प्लस-वन रणनीति और मूल सीमा शुल्क बढ़ाकर 70 प्रतिशत किए जाने से भारत के खिलौना उद्योग में तेजी आई है। बीआईएस मानक चिन्ह वाले खिलौनों के निर्माण के लिए

बीआईएस ने घरेलू निर्माताओं को 1200 से अधिक लाइसेंस और विदेशी निर्माताओं को 30 से अधिक लाइसेंस प्रदान किए हैं। सरकार के प्रयासों से भारतीय खिलौना उद्योग के लिए अधिक अनुकूल विनिर्माण परितंत्र बनाने में मदद मिली है। 2014 से 2020 तक 6 वर्षों की अवधि में सरकार के समर्पित प्रयासों से विनिर्माण इकाइयों की संख्या दोगुनी हो गई है, आयातित वस्तुओं पर निर्भरता 33 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत हो गई है। वर्तमान में एमएसएमई मंत्रालय 19 खिलौना उत्पादन केंद्रों की मदद कर रहा है, और वस्त्र मंत्रालय 13 खिलौना उत्पादन केंद्रों को खिलौनों का डिजाइनिंग तैयार करने और जरूरी साधन मुहैया करने में मदद कर रहा है। स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रचार पहल भी की गई हैं, जिनमें दि इंडियन टॉय फेयर 2021, टॉयकैथैरन आदि शामिल हैं। विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने घटिया स्तर के खिलौनों के आयात पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक आयात खेप का नमूना परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014-15 के बाद से लगातार वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट तक में सरकार ने खिलौना उद्योग के विकास के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन और समर्थन देने की रणनीतिक पहल की है। सरकार ने खिलौना उद्योग को देश के 24 प्रमुख सेक्टर में स्थान दिया है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय खिलौनों को वैश्विक खिलौना बाजार में बड़ी भूमिका निभाने हेतु खिलौना उद्यमियों को प्रेरित किया गया है। निश्चित रूप से मेक इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सरकार की नीतिगत पहलों के साथ-साथ घरेलू निर्माताओं के प्रयासों से भारतीय खिलौना उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि देश का खिलौना उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी देश के खिलौना सेक्टर को चमकीली ऊंचाई देने के लिए खिलौना क्षेत्र के तहत एक लम्बे समय से चली आ रही कई बाधाओं को हटाया जाना जरूरी है।



संक्षिप्त समाचार

युवक पर चाकू से हमला करने  
वाला आरोपी गिरफतार

धमतरी(विश्व परिवार)। जिले के कोतवाली पुलिस के टीम ने युवक पर चाकू से प्रणालीक हमला करने वाला आरोपी को गिरफतार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से बटादार चाकू जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित का आरोपी के शासीशुदा बहन के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसको पीड़ित पहले अपने साथ भगा कर ले गया था। कुछ दिन बाद वापस आने के बाद आरोपी के परिजन उनको सम्मान भेज दिये थे। पीड़ित द्वारा प्रेम प्रसंग के लिए बहन के नाम के लिए खावये गोदान को पोहले के लोगों को दिया था। इससे आरोपीओं को शमिदी महसूस होता था। उसी बात के गुस्से एवं पुराने रंगिश को लेकर कल आरोपी अजय सिंह 23 वर्ष निवासी सुंदरांज वार्ड सिहावा के द्वारा प्रार्थी को देखकर धारादर स्थिरगंगदार चाकू से हमला करने के नियत से प्राप्तानक बार कर प्रार्थी के बांधे पीठ, दाहिने से बाले आरोपी को घुसा देखा जा रहा है। प्रार्थी को परिजन लोग इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। वहाँ पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर जेल भेज दिया है।

डीएसपी चन्द्रा ने मार्ग में बैठे  
रहने वाले अवारा मवेशियों को  
पकड़कर भेजा कांजी हाउस

धमतरी(विश्व परिवार)। पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री अंजिन वाणीय के नियन्त्रण पर यातायात उप पुलिस अधीक्षक श्री मंणीशंकर चन्द्रा के द्वारा शहर के मार्ग में बैठे व घुमने वाले अवारा मवेशियों के जमघत से होने वाले परेशानी व जाम को दूर करने, मवेशी मुक्त मार्ग, निवारण व दूर्घटनाहित मार्ग बनाने के उद्देश्य से हमराह स्टॉफ़ के साथ नारपालिक निगम के कार्यालय के बाहर कर शहर के मार्ग में बैठे व घुमने वाले अवारा मवेशियों का धरपकड़ अधिकार चन्द्रा जा रहा है। इसी दौरान दिनांक 01.05.2024 के रात्रि में उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री मंणीशंकर चन्द्रा के द्वारा यातायात स्टॉफ़ एवं नगर निगम काउंसिल कैचर टीम के साथ शहर के अर्जुनी मोड़ से राजांचांथा तक कुल 20 अवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस भिजवाया गया। यातायात पुलिस मवेशी मालिकों से अपील करती है, कि अपने मवेशियों को खुला न छोड़ें, मवेशी का मार्ग में होने से जन एवं पशुधन हानि होती है तथा यातायात बाधित रहती है। यातायात व्यवस्था बनाने में यातायात पुलिस का सहयोग करें। उक्त कार्यालयी के दौरान यातायात स्टॉफ़ उनि.के.आर.साहू, प्रभारी उत्तम साहू, चालक आरक्षक संसोध ठाकुर, एवं नगर निगम काउंसिल कैचर टीम से चम्पर चंदेल, गोविंद एवं श्यामू उपस्थित रहे।

शादी का झांसा देकर  
नाबालिक से बलात्कार  
आरोपी गिरफतार

कोरियां(विश्व परिवार)। एक नाबालिक लड़कों को शादी का प्रलोग देकर उनके साथ लगातार दृष्टव्य करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित लड़की ने 30 अप्रैल को थाने में शिकायत दर्ज की थी कि माह अप्रैल 2023 में नाबालिक कार्यक्रम में अपने चाही तथा महराजपुरहीन दीदी के साथ मैर्ग थी। जहाँ इसकी मुलाकात आरोपी छवीलाल से हुई और उसे उसके साथ कहकर किया गया है। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ कहकर किया गया है। इसके बाद आरोपी ने छवीलाल ने पीड़ित से यह कहकर किया, मैं तुम्हें पर्संद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता उसके साथ कह कर शारीरिक संबंध बनाये। जिससे जब आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया। जिसपर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपाराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

कुकड़ाझोर में किया  
गया निःशुल्क मेडिकल  
कैम्प का आयोजन

नारायणपुर(विश्व परिवार)। 53वीं वाहिनी आईटीबी जेलवाडी, नारायणपुर के द्वारा 30 अप्रैल को सीओओ बुकड़ाझोर में अग्रिम भाटी कमांडेट 53वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के कुशल मार्ग दर्शन में एवं जिला जिलाकारी, नारायणपुर के सहयोग से डॉक्टर सपना के नेतृत्व में नियुक्त मेडिकल कैम्प का आयोजन किया गया। वाहिनी आईटीबी की जिलाकारी के नजदीक गाँवों की विकास कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया गया।

# बिरहोर आदिवासियों के बीच पहुंचे कलेक्टर

मांदर की थाप पर कलेक्टर और बिरहोर आदिवासियों ने मनाया मतदाता जागरूकता का उत्सव

कलेक्टर ने दिलाई मतदाता शपथ,  
वोटरों का किया समान



भी बिरहोर आदिवासियों के साथ मांदर बजाया। उन्होंने मतदाता जागरूकता संदेश के गुब्बरे भी आसमान में छोड़े। कार्यक्रम में 22 पंचायतों से पहुंच बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। महिला-पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किंग ग्रैन नूट्स ने समाज विधि दिया। पंचायत बचन के पास कार्यक्रम स्थल को पूरी तरह से जनजाति परिवेश में सजाया गया था। उन्होंने किया है कि कोटा जनपद पंचायत में बिरहोर जनजाति के 104 परिवारों के 336 सदस्य निवासरह हैं। बिरहोर जनजाति का यह नुत्य लोगों की बीच एक जुटा की भावना पैदा करता है। कलेक्टर ने सभी से मतदाता अपील की। कलेक्टर ने सभी को मतदाता शपथ दिलाई। सभी को मतदाता केंद्र में आना अपकी जिम्मेदारी है और मतदाता अच्छे से करवाना हमारी अर्थात् प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मतदाता केंद्र में भीषण गर्भी को देखते हुए त्रिपुरा एवं मतदाताओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिम्मेदारी की उत्साह दिलाई। सभी को मतदाता शपथ दिलाई।

## समान कार्य का समान वेतन पाना श्रमिक का अधिकार - जिला न्यायाधीश कोटा

कोटा(विश्व परिवार)। 01 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय त्रिम दिवस के अवसर पर यातायात उप पुलिस अधीक्षक श्री मंणीशंकर चन्द्रा के द्वारा शहर के मार्ग में बैठे व घुमने वाले अवारा मवेशियों के जमघत से होने वाले परेशानी व जाम को दूर करने, मवेशी मुक्त मार्ग, निवारण व दूर्घटनाहित मार्ग बनाने के उद्देश्य से हमराह स्टॉफ़ के साथ नारपालिक निगम के कार्यालय के बाहर कर शहर के मार्ग में बैठे व घुमने वाले अवारा मवेशियों का जागरूकता विधि का आयोजन किया गया। इसी दौरान दिनांक 01.05.2024 के रात्रि में उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री मंणीशंकर चन्द्रा के द्वारा यातायात स्टॉफ़ एवं नगर निगम काउंसिल कैचर टीम के साथ शहर के अर्जुनी मोड़ से राजांचांथा तक कुल 20 अवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस भिजवाया गया। यातायात पुलिस मवेशी मालिकों से अपील करती है, कि अपने मवेशियों को खुला न छोड़ें, मवेशी का मार्ग में होने से जन एवं पशुधन हानि होती है तथा यातायात बाधित रहती है। यातायात व्यवस्था बनाने में यातायात पुलिस का सहयोग करें। उक्त कार्यालयी के दौरान यातायात स्टॉफ़ उनि.के.आर.साहू, प्रभारी उत्तम साहू, चालक आरक्षक संसोध ठाकुर, एवं नगर निगम काउंसिल कैचर टीम से चम्पर चंदेल, गोविंद एवं श्यामू उपस्थित रहे।

## तेंदूपता तोड़ने गए दो ग्रामीण डीआईजी डीआर आचला के सेवानिवृत होने पर दी गई विदाई

### भालू के हमले से घायल

गरियांबंद(विश्व परिवार)। गुरुवार सुबह जिला मुख्यालय से लगे ग्राम योगदान करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित लड़की ने 30 अप्रैल को थाने में शिकायत दर्ज की थी कि माह अप्रैल 2023 में नाबालिक कार्यक्रम में अपने चाही तथा महराजपुरहीन दीदी के साथ मैर्ग थी। जहाँ इसकी मुलाकात आरोपी छवीलाल से हुई और उसके साथ कहकर किया गया है। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ कहकर किया गया है। इसके बाद आरोपी ने छवीलाल ने पीड़ित से यह कहकर किया, मैं तुम्हें पर्संद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता उसके साथ कह कर शारीरिक संबंध बनाये। जिससे जब आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया। जिसपर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपाराध कायम कर विवेचना की गयी।

उनके कार्यों, व्यवहार  
एवं उपलब्धियों की  
सभी ने की सराहना

बालोद(विश्व परिवार)। पुलिस

उप महानिरीक्षक एवं छत्तीसगढ़

सशस्त्र बल 14वीं वाहिनी धोरो

के कारण के सेनानी डीआर आचला

के 30 अप्रैल को अर्द्धवार्षिकी

आयु पूरा के परिवर्तने के पश्चात् बुधवार 01 मई को 14वीं वाहिनी धोरो

के परियोग में आयोजित विदाई

समारोह में उन्हें विवाह दी गई।

इस अवसर पर उपस्थित सभी

लोगों ने आचला के शून्य से

शिखर तक के बात्रा की प्रसंशा

करते हुए उनके कार्यों, व्यवहार

एवं उपलब्धियों की भूरी-भूरी

सराहना की। उल्लेखनीय है कि आचला मोहला-मानपुर-अंबागढ़



## सन्मति नगर दिग्म्बर जैन खण्डेलवाल समाज द्वारा नवल बाई दीपचंद बड़जात्या छात्रावास भवन का भूमि खनन कार्य प्रारंभ किया गया



रायपुर (विश्व परिवार)। फारांडोह सन्मति नगर श्री दिग्म्बर जैन खण्डेलवाल पंचायत समिति के द्वारा नवल बाई दीपचंद बड़जात्या छात्रावास भवन निर्माण कार्य दिनांक 2 मई 2024 को पूरे विधिवान रूप से शुरू किया गया। पंचायत के अध्यक्ष अरविंद बड़जात्या ने बताया कि लगभग 29000 फिट भूमि में गार्डन, पार्किंग, चार मंजिला छात्रावास भवन निर्माण कार्य का खनन मुहूर्त गणनी मात्रा जी सौभाग्यमति

जी के संघ की पावन निशाय में सकल दिग्म्बर जैन समाज की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि स्व ताराचंदजी बड़जात्या परिवार निवासी रायपुर, खामगांव, वर्धा के द्वारा ये भूमि दान में दी गई थी। जिसमें आधुनिक सीढ़ी से निर्माण किया जाएगा, चौथे माले में किंवदं भूतल में पार्किंग, गार्डन, भूतल में सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।